1

UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

by

GS Paper – III : INTERNAL SECURITY

Dr. S. S. Pandey

2

Dr. S. S. Pandey

Development and Spread of Extremism

3

Development and Spread of Extremism

- भारत में विकास एवं इसमें निहित असंतुलन
- भारत में विकास एवं फैलते उग्रवाद में संबंध
- आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतिया
- आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के कारण
  - आतंकवाद
  - उग्रवाद
  - नक्सलवाद
  - अलगाववाद
  - क्षेत्रवाद
  - भाषावाद
  - सम्प्रदायवाद
  - जाति संघर्ष
- चुनौतियों के समाधान हेतु किए गए प्रयास
  - संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास
  - आयोग एवं परिषद्
  - विभिन्न समितियाँ
  - नीतिगत एवं योजनागत प्रयास
  - अन्य प्रयास
- समीक्षा एवं सुझाव

4

Dr. S. S. Pandey

Security Challenges Extremism – Naxalism (Left-Wing Extremism)

5

UPSC – CSE में पूछे गए प्रश्न

6

- नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15/2022

7

- भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? (250 शब्द) 15/2020

8

- वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परन्तु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। (2018)

9

- पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। (2015)

10

- भारत के संविधान की धारा 244, अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी पांचवीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरम पंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (2013)

11
Security Challenges
Extremism – Naxalism
(Left-Wing Extremism)
Dr. S. S. Pandey

16
व्लादिमीर लेनिन
रूस

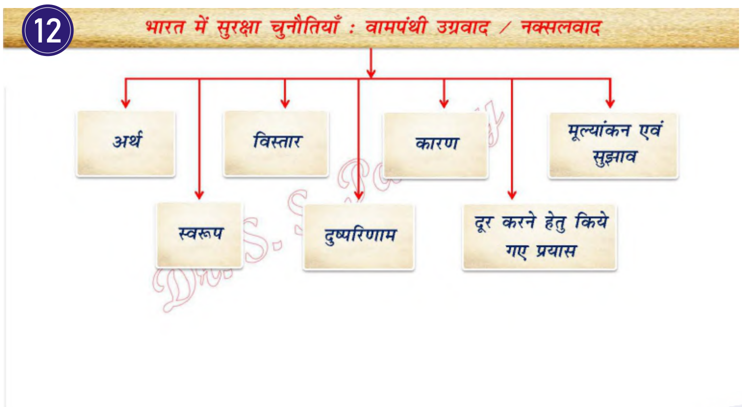
12
भारत में सुरक्षा चुनौतियाँ : वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद
अर्थ
विस्तार
कारण
मूल्यांकन एवं सुझाव
स्वरूप
दुष्परिणाम
दूर करने हेतु किये गए प्रयास

17
माओ से-तुंग
चीन

13
वामपंथी उग्रवाद
या
नक्सलवाद का अर्थ

18
जंगल संथाल

14
वामपंथी विचारधारा
वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन जो हिंसक क्रांति द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है।

19
कानू सन्याल
CPI (ML)

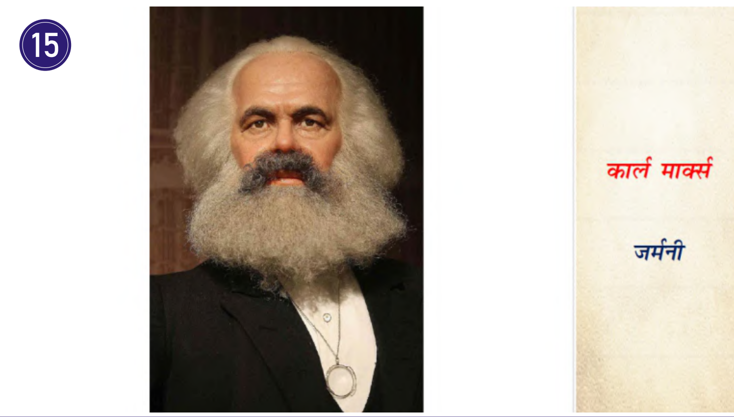
15
कार्ल मार्क्स
जर्मनी

20
चारू मजूमदार
CPI (ML)

KGS IAS

21

कन्हाई चटर्जी

MCC

22

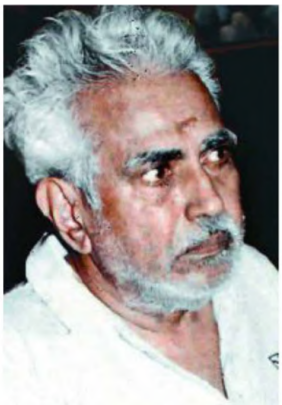

कोंडापल्ली सीतारमैया

PWG

23

वामपंथी उग्रवाद का स्वरूप

24

(i)

आर्थिक विषमता एवं शोषण के विरूद्ध भूमिहीनों द्वारा प्रारंभ

25

(ii)

कालान्तर में जनजातीय असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार

26

(iii)

वैचारिक आधार पर हिंसक आंदोलन

27

(iv)

गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के रूप में संचालित

28

1967

CPI (ML)

29

1975

MCC

30

1980

PWG

31

2000

पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी

32

2004

CPI (M)

33

भारत में नक्सलवाद का विस्तार

34

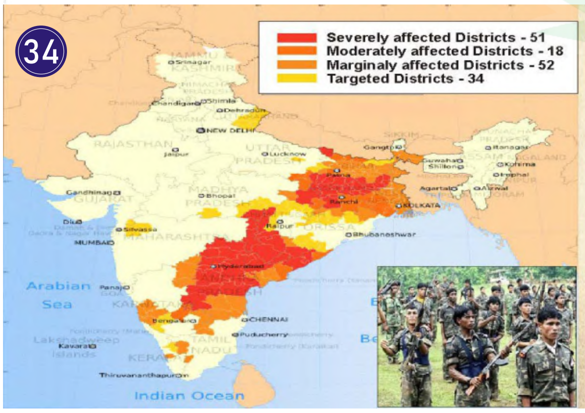

Red Corridor

35

(i)

14 राज्यों के 165 जिलों में क्रियाशील

(2021- 70 जिलों में)

2013 में 76 जिलों में नक्सली हिंसा की रिपोर्ट आई थी, जबकि 2020 में यह संख्या घटकर 53 और 2021 में 41 हो गयी

36

(ii)

50 हजार नियमित तथा 20 हजार अतिरिक्त सशस्त्र नक्सली कैडर

37

(iii)

सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 35 से घटकर 30 हो गयी और जुलाई, 2021 में कम होकर 25 हो गयी

38

2018 के मुकाबले 2022 में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 39% की कमी आई है

MHO

39

भारत में प्रमुख नक्सली घटनाएँ

40

15 नवंबर 2005

रात करीब नौ बजे एक हजार नक्सलियों द्वारा बिहार के जहानाबाद जेल पर हमला

नक्सली अजय कानू समेत सैकड़ों कैदियों को छुड़ाकर फरार

इस दौरान करीब साढ़े तीन सौ अन्य कैदी भी फरार

41

27 अक्टूबर 2009

नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के जंगलमहल में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 5 घंटे तक रोके रखा

42

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का विस्तार एवं नक्सली घटनाएँ

43

6 अप्रैल 2010

दंतेवाड़ा नक्सली हमला CRPF के 76 जवानों की मृत्यु

44

25 मई 2013

झीरमघाटी नक्सली हमला कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला सहित 27 लोगों की मृत्यु

45

11 मार्च 2014

सुकमा में नक्सली हमला

11 जवान सहित 16 लोगों की मृत्यु

46

1 दिसंबर 2014

सुकमा में नक्सली हमला

13 जवान शहीद

47

19 जुलाई 2016

बिहार के गया में नक्सली हमला

10 जवान शहीद

48

11 मार्च 2017

सुकमा में नक्सली हमला

13 जवान शहीद

49

24 अप्रैल 2017

सुकमा में नक्सली हमला

25 जवान शहीद

50

13 मार्च 2018

सुकमा में नक्सली हमला

9 जवान शहीद

51

23 सितंबर 2018

आंध्र प्रदेश में नक्सली हमला

TDP MLA की हत्या

56

31 जनवरी 2024

बीजापुर में नक्सली हमला

3 जवान शहीद

52

9 अप्रैल 2019

दंतेवाड़ा नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी मारे गए

57

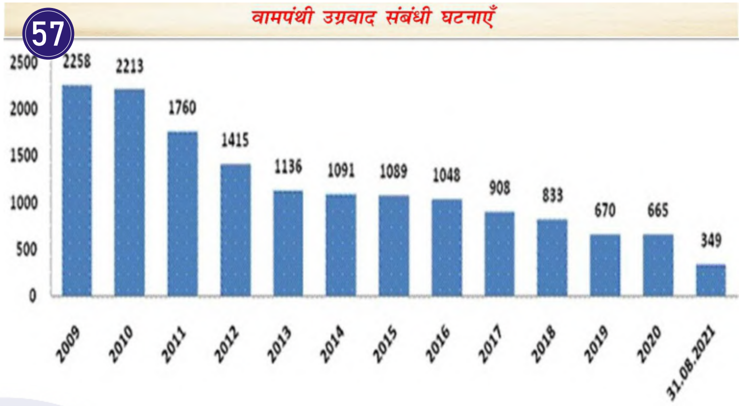

53

1 मई 2019

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला

16 जवान शहीद और 10 जवान घायल

58

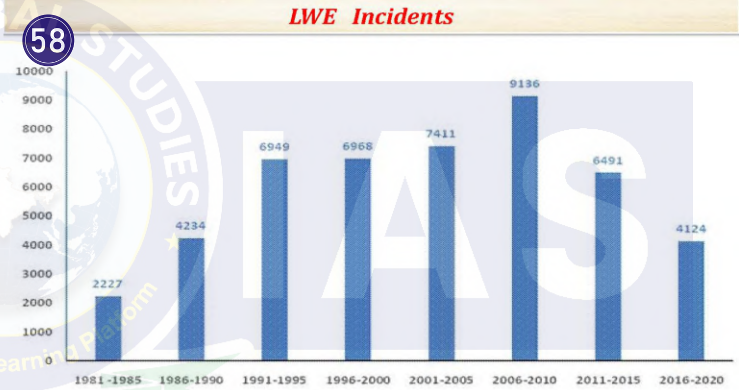

54

3 अप्रैल 2021

छत्तीसगढ़ के सुकमा-बीजापुर नक्सल हमला

22 जवान शहीद

59

55

25 अप्रैल 2023

दंतेवाड़ा में नक्सली हमला

10 जवान शहीद

60

वामपंथी उग्रवाद के दुष्परिणाम

Dr. S.

61

(i) जानमाल की हानि एवं भय का माहौल

(ii) विकास दुष्प्रभावित

(iii) कानून व्यवस्था की समस्या

(iv) अपराधियों एवं देश विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन

62

(v) सामुदायिक सौहार्द्रता कमजोर

(iv) देश की एकता एवं अखण्डता को खतरा

(vii) देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब

63

वामपंथी उग्रवाद के कारण

64

(i) अन्यायपूर्ण कृषक संरचना एवं आर्थिक विषमता

(ii) भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता

(iii) सामंती मनोवृत्ति एवं जातिगत शोषण

65

(iv) जनजातियों में गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं भूमि हस्तांतरण

(v) विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण द्वारा जनजातियों का विस्थापन, इनकी वन आधारित आर्थिकी का विनाश एवं खनिज संपदा का दोहन

66

(vi) 5वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार अधिनियम आदि के समुचित क्रियान्वयन की कमी

(vii) भ्रष्टाचार तथा प्रशासन एवं आम जनता के बीच बढ़ती दूरी

(viii) उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, महत्वाकांक्षा में वृद्धि एवं तुलनात्मक अभावबोध

67

(ix) विदेशी शक्तियों की भूमिका

(जूलाई 2017 में माओवादी नेता रामाकृष्ण राव एवं पोलित ब्यूरो के सदस्य वेनूगोपाल राव अरुणाचल प्रदेश में चीनी गुप्तचरों के नेतृत्व में होने वाले मीटिंग में शामिल हुए)

68

वेनूगोपाल राव

69

(x) राजनीतिक दलों एवं शहरी नक्सल की नकारात्मक भूमिका

(2018 में 6 लोगों - पी. वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, वेरनोन गोन्जाल्विस, प्रो. जी.एन. साईबाबा और अरुण परेरा की पुणे पुलिस द्वारा नक्सल कनेक्सन के आरोप में गिरफ्तार किया गया तबसे नक्सलवाद के कारण के रूप में शहरी नक्सल की चर्चा प्रमुख है)

70

पी. वरवर राव

71

सुधा भारद्वाज

72

गौतम नौलखा

73

वेरनोन गोन्जाल्विस

74

प्रो. जी.एन. साईबाबा

75

अरुण परेरा

76

वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास

↓

77

गृह मंत्रालय

78

2006

गृह मंत्रालय द्वारा, 'नक्सल प्रबंधन विभाग' का गठन

79

नीतिगत प्रयास

↓

80

1. भारत सरकार की वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद पर नीति, 2014

↓

चार आयामी रणनीति पर बल

(i) सुरक्षा
(ii) विकास
(iii) स्थानीय समुदायों की हकदारी
(iv) जन अवधारणा प्रबंधन

81

2. मई 2017 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए समाधान (SAMADHAN) के रूप में नया फॉर्मूला दिया–

- S -smart leadership
- A -aggressive strategy
- M -motivation and training
- A -actionable intelligence
- D -dashboard based key performance indicators and key result areas
- H -harnessing technology
- A -action plan for each threat
- N -no access to financing

86

4.

2013

LARR Act

Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Bill, 2013

www.realthorizon.com

82

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास

87

योजनागत प्रयास

83

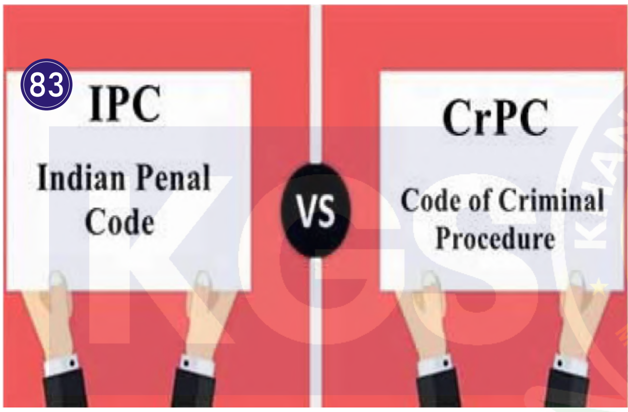

1.

IPC (1860) & CRPC (1973) के प्रावधान एवं UAPA - 1967 के प्रावधान

88

1.

सामाजिक न्याय से युक्त विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

84

2.

2006

वन अधिकार अधिनियम

89

2.

नक्सली क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

85

3.

2000

झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ के रूप में नए राज्यों का गठन

90

(i)

2007

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड योजना

91

(ii)

2011

प्रधानमंत्री ग्राम विकास फेलोशिप कार्यक्रम

92

(iii)

2012

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना

(2020-21 में 9 राज्यों को 304.49 करोड़)

93

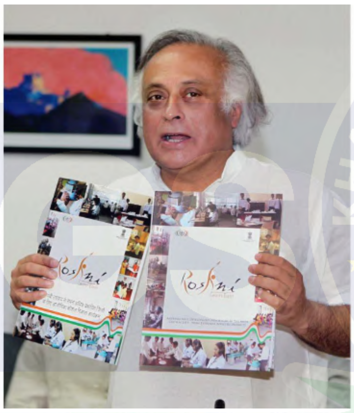

(iv)

2013

रोशनी परियोजना

94

(v)

2015

नक्सल प्रभावित जिलों में Livelihood College की स्थापना

95

(vi)

2016

विशेष अवसंरचना योजना (SIS)

(75:25 केन्द्र राज्य की भागीदारी)

96

(vii)

मई, 2016

नरेन्द्र मोदी द्वारा रायपुर में बस्तर क्षेत्र के लिए 24000 करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजना की शुरूआत

97

(viii)

सितम्बर, 2021

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 17600 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी, जिसमें 9343 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा

98

(ix)

दूर संचार सुविधाओं में सुधार के लिए 2343 + 4072 नए मोबाइल टावर और 18 महीने में 2542 अतिरिक्त टावर लगाने का लक्ष्य

99

(x)

वित्तीय समावेशन हेतु 4903 डाकघर, 1253 बैंक शाखाएँ 1264 एटीएम और 16806 बैंकिंग प्रतिनिधि (BC) केन्द्र खोले गए हैं

100

(xi)

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कुल 234 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत और इनमें से 119 कार्यरत

(xii)

सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण

(2+2.5 करोड़ / PS की दर से 650 PS का निर्माण प्रारंभ)

(xiii)

सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA)

(2017-18 में 175 करोड़)

(xiv)

'वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन स्कीम के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना'

(2020-21 में 69.35 करोड़ का आवंटन)

3.

विश्वास बहाली एवं जनसहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास

(i)

नक्सलियों से बातचीत

(ii)

'आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति' के तहत–

- 1.5-2.5 लाख प्रति नक्सली तत्काल अनुदान (3 वर्ष बाद प्राप्त)
- 4000 प्रतिमाह वजीफा (3 वर्ष तक)
- कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

(iii)

नक्सली हिंसा से पीड़ितों को 3 लाख वित्तीय सहायता

(iv)

सामुदायिक एवं पुलिसिंग नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (CAP)

मुख्य उद्देश्य–

सुरक्षा बलों के मानवीय चेहरा को प्रदर्शित करना

(v)

मीडिया योजना

(राजीव कुमार द्वारा– 'प्रत्यावर्तन : द होम कमिंग' नामक फिल्म का निर्माण)

(vi)

2021

SAHAY योजना (स्पोर्ट्स एक्शन ट्वर्डस हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ)

झारखंड सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना की शुरूआत

111

4.

सुरक्षा बलों एवं आसूचना एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण

112

(i)

CRPF के 116 बटालियन (9 कोबरा बटालियन सहित) की तैनाती तथा 5 ITBP की तैनाती

113

(ii)

कोया कामांडो (2006), स्पेशल टॉस्क फोर्स, ग्रेहाउंड्स (1989) आदि का गठन

114

(iii)

2008

छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में उस जिले के लोकल लोगों की District Reserve Guard के रूप में भर्ती

115

(iv)

मई, 2015 'विकास संघर्ष समिति' (सलवा जुडूम-2) का गठन

116

(v)

10 राज्यों में 56 'इण्डिया रिजर्व बटालियन' को मंजूरी जिसमें 38 का गठन

117

(vi)

अगस्त, 2016 CRPF के 'बस्तर बटालियन' का निर्माण प्रारंभ (क्षेत्रीय लोगों की बहाली, 1/3 महिलाएँ)

2018 में 2 बटालियन की तैनाती

118

(vii)

5 विद्रोहरोधी एवं आतंकवादरोधी (CIAT) विद्यालय की स्थापना

119

(viii)

जनवरी, 2021 में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में CRPF की 5 नई बटालियन तैनात

120

5.

विभिन्न ऑपरेशन एवं गिरफ्तारी

121

(i)

ऑपरेशन बुर्का (पश्चिम बंगाल में), ऑपरेशन ग्रीन हंट-2009 (कोबरा के सहयोग से छत्तीसगढ़ में), ऑपरेशन नयी दिशा-2014 (झारखण्ड में), KC-60 द्वारा नक्सल विरोधी अभियान (2018 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में) ऑपरेशन प्रहार (2017 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में)

122

(ii)

2021

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरूद्ध ऑपरेशन मॉनसून प्रारंभ

123

(iii)

पुणे पुलिस द्वारा 2018 में 6 बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी जिन पर नक्सलियों को मदद करने का आरोप

(इनके लिए 'Urban Naxals' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है)

124

पी. वरवर राव

(कवि, शिक्षक एवं लेखक)

तेलंगाना

125

सुधा भारद्वाज

(ट्रेड यूनियन नेता एवं वकील)

छत्तीसगढ़

126

गौतम नौलखा

(मानवाधिकार कार्यकर्त्ता एवं पत्रकार)

दिल्ली

127

वेरनोन गोन्जाल्विस

(अर्थशास्त्र के प्रोफेसर)

मुंबई महाराष्ट्र

128

अरुण फरेरा

(वकील)

मुंबई महाराष्ट्र

129

प्रो. जी.एन. साईबाबा

(प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी)

दिल्ली

130

(iv)

2020 में लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आइये)

(छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में)

131

132

(v)

नवंबर 2022 वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये CRPF द्वारा Forward Operative Bases (FOB) का निर्माण प्रारंभ और मार्च 2024 तक 25 FOB का निर्माण

133

(vi)

2 अप्रैल 2024

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया

134

(vii)

7 अप्रैल 2024

बस्तर में तेलंगाना ग्रेहाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में तीन नक्सली मारे गये

135

समीक्षा एवं सुझाव

136

A.

उपलब्धियाँ / सफलता के बिन्दु

137

निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद में कमी आयी है, जैसे–

138

1.

2010 में 2213 नक्सली घटनाएँ जिसमें 1005 मौत जबकि 2020 में मात्र 665 घटनाएँ एवं 183 मौत

139

वामपंथी उग्रवाद संबंधी घटनाएँ

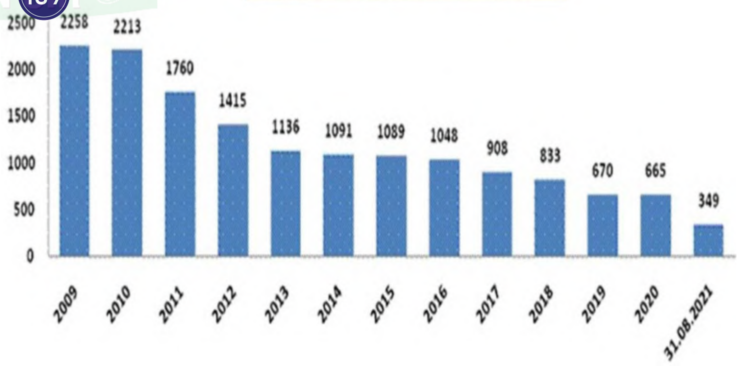

140

नक्सली हिंसा के परिणामस्वरूप मौतें

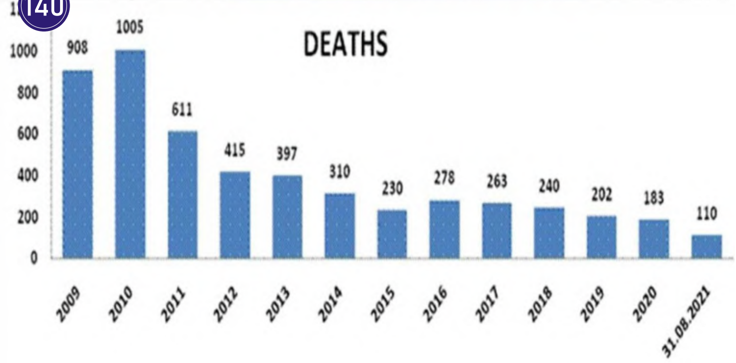

2.

7 नवंबर 2022 को गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जारी जिसके अनुसार–

(i)

बीते आठ वर्षों में नक्सली हिंसा में 55% की कमी आई है और इससे मौतों की संख्या में 63% की कमी आई है

(ii)

2020 की तुलना में 2021 में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 24% (665 से घटकर 509) और मौतों में 20% (183 से घटकर 147) कमी आई है

(iii)

नक्सल कैडर को खत्म करने के दर में 65% वृद्धि तथा नक्सलियों के आत्मसमर्पण की दर में 185% की वृद्धि

(iv)

2015 से 2020 के बीच करीब 900 नक्सली मारे गए एवं 4200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

(वार्षिक रिपोर्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

3.

नवम्बर, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव में नक्सलियों के विरोध के बावजूद 70% मतदान

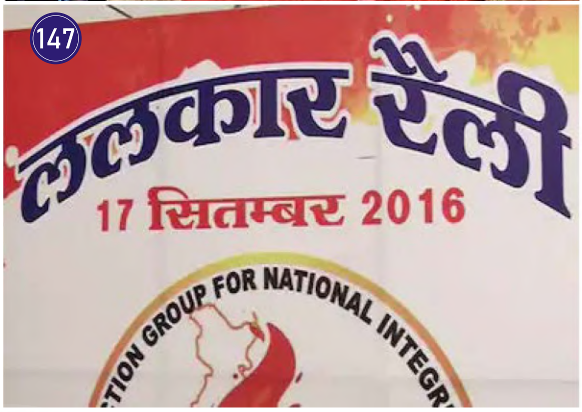

4.

6 सितम्बर, 2016 बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ 'ललकार रैली' – 50 हजार लोग शामिल

148

B.

असफलता के बिन्दु

परन्तु अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर और वामपंथी उग्रवाद की समस्या जारी, जैसे-

1.

24 अप्रैल, 2017- सुकमा में नक्सली हमला, 25 जवान शहीद

151

2.

13 मार्च, 2018– सुकमा में नक्सली हमला, 9 जवान शहीद तथा 23 सितम्बर 2018 को आंध्र प्रदेश में TDP MLA की नक्सलियों द्वारा हत्या

152

3.

3 अप्रैल 2021– छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद

153

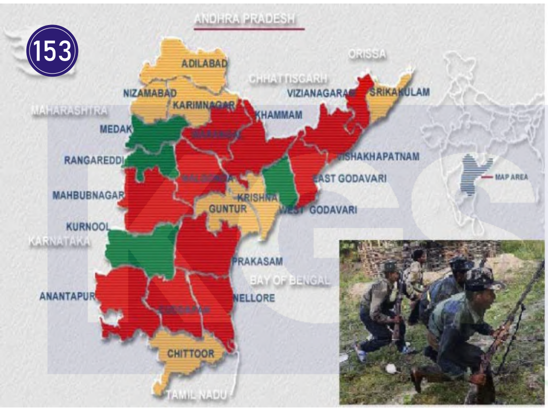

4.

छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद में वृद्धि हुई है

(छत्तीसगढ़ का बस्तर, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम् एवं पश्चिमी गोदावरी जिला, उड़ीसा का रायगढ़ एवं कलाहांडी जिला में मुख्यत:)

154

5.

केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नया आधार बनाने का प्रयास

155

6.

11 सितम्बर, 2016

मानवाधिकार आयोग ने जाँच में पाया – झारखण्ड में आत्मसमर्पण घोटाला

156

C. सुझाव

157

1. दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ प्रयास हो
2. विकास में सामाजिक न्याय की स्थापना तथा भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो

158

3. भूमि सुधार कार्यक्रम का समुचित क्रियान्वयन हो और इस हेतु-
   - इसमें समाजिक न्याय की स्थापना हो
   - इसका आर्थिक सुधार / उदारीकरण के साथ समायोजन स्थापित किया जाय

159

4. 5वीं अनुसूची के प्रावधान, वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा LARR Act, 2013 का सही क्रियान्वयन हो
5. सुरक्षाबल एवं आसूचना एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण एवं इनके मनोबल में वृद्धि की जाए

160

6. पुलिस के प्रति आम जनता के विश्वास में वृद्धि की जाए
7. नक्सलवाद के विरूद्ध जनमत का निर्माण एवं नक्सलवाद के उन्मूलन में जनसहभागिता में वृद्धि की जाए
8. शहरी नक्सलवाद को हतोत्साहित किया जाए

161

संभावित प्रश्न

162

1. भारत में वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए और इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

163

2. विभिन्न सरकारी तथा अन्य प्रयासों के बावजूद आज देश में वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय या सुझाव प्रस्तुत करेंगे?

164

3. भारत में वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद के कारणों की चर्चा कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग और जन भागीदारी में वृद्धि इस समस्या का कारगर उपाय हो सकता है? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

165

4. "वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या सरकार के असंतुलित विकास नीतियों का परिणाम है।" आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? उत्तर दीजिए।

166

5. "वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या ने भारत के आर्थिक-सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है।" इस कथन के संदर्भ में नक्सलवाद के दुष्परिणामों पर विचार कीजिए।

167

6. "भारत में वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या का समाधान संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास है न कि तीव्र पुलिस प्रतिक्रिया।" समीक्षा कीजिए।

168

7. भारत में वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद आज एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय हो चुका है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिए एवं इसके समाधान हेतु किए गए सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

169

8. वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या ने भारत के समक्ष आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है। इस कथन के प्रकाश में वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद के दुष्परिणामों पर विचार कीजिए।

170

9. भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद से किस प्रकार संबंधित है? उत्तर दीजिए एवं इस संदर्भ में उपयुक्त उपाय सुझाइए।

171

10. भारत में अक्सर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाना, वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद के उद्भव एवं विकास का एक प्रमुख कारण रहा है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।

172

11. भारत सरकार की वन नीति वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद के उद्भव व विकास से किस प्रकार संबंधित है? वन अधिकार अधिनियम 2006 वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या के समाधान में कहाँ तक कारगर हो सकता है? उत्तर दीजिए।

173

12. भारत में भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या के उद्भव एवं विकास का प्रमुख कारण रहा है। इस कथन को सविस्तार प्रतिपादित कीजिए एवं इस संदर्भ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के महत्व पर प्रकाश डालिए।

174

13. 'शहरी नक्सल' के उन्मूलन के बिना भारत में नक्सलवाद / वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन संभव नहीं है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर दीजिए।

175

14. तीव्र विकास और विकास की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की हकदारी को सुनिश्चित किए बिना वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इस कथन पर चर्चा कीजिए और इस दिशा में किए गए सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

176

15. 'जन अवधारणा प्रबंधन' वामपंथी उग्रवाद की समस्या-समाधान की दिशा में भारत सरकार की प्रमुख रणनीतियों में शामिल है। भारत सरकार की इस रणनीति की प्रासंगिकता को दर्शाइए और इस दिशा में किए गए सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

177

UPSC - CSE में पूछे गए प्रश्न

178

1. भारत के संविधान की धारा 244, अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी पांचवीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरम पंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (2013)

179

2. पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। (2015)

180

3. वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परन्तु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2018)

181

4. भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? (2020)